



युवा शक्ति को मिला सुशासन का साथ गुजरात बना देश का स्वर्णअप हब

“स्टर्टअप को प्रोत्साहन देकर ગુજરાત સરકાર ને યુવાઓં કો આત્મનિર્ભર બનાને કી દિશા મેં ક્રાંતિકારી પહલ કી હૈ।” -શ્રી હર્ષ સંઘવી, માનનીય ઉપમુખ્યમંત્રી, ગુજરાત

मेट्रो से मिलेगी राहत की सांस, प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा दांव

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में लगातार गंभीर होते वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को प्रदूषण नियंत्रण की धुरी बनाते हुए बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। सरकार का साफ मानना है कि जब तक निजी वाहनों पर निर्भरता कम नहीं होगी, तब तक प्रदूषण पर प्रभावी लगाम लगाना संभव नहीं है। इसी सोच के तहत दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के विस्तार और परिवहन ढांचे को मजबूत करने के लिए परिवहन बजट में ऐतिहासिक बढ़ोत्तरी की गई है, जिसे सरकार आने वाले वर्षों के लिए गेमचेंजर मान रही है।

मिलगा, बल्कि चल रहा परियाजनाआमें भी किसी तरह की वित्तीय बाधा नहींआने दी जाएगी।

The image is a composite of two photographs. The left side shows a white metro train with a red circular logo containing a horizontal line and the number '8' below it. The right side shows a woman with dark hair tied back, wearing glasses, a red sari with a white floral pattern, and a red bindi. She is seated at a table, looking towards the camera. A small blue object is visible in her hands.

दिल्ली कैबिनेट ने मेट्रो रेल ट्रांजिट सिस्टम के फेज-IV के तहत तीन महत्वपूर्ण कॉरिडोर—लाजपत नगर से साकेत, इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ और रिठाला से कुंडली—को मंजूरी दे दी है। इन कॉरिडोरों के पूरा होने से दिल्ली के कई घनी आबादी वालाओं के साथ-साथ एनसीआर क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में भी बड़ा सुध

होगा। सरकार का मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी से लाखों लोग रोजमर्रा की आवाजाही के लिए निजी वाहनों की बजाय मेट्रो को अपनाएंगे, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव घटेगा और प्रदूषण में स्वाभाविक कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार मेट्रो के फेज-I, फेज-II और फेज-III से जुड़ी लगभग 2,700 करोड़ रुपये की पुरानी देनदारियों को भी चुकाने के लिए प्रतिबद्ध है। चालू वित्त वर्ष में ही 940 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं, ताकि दिल्ली मेट्रो की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी रहे और भविष्य की परियोजनाओं में किसी तरह की रुकावट न आए। सरकार का उद्देश्य मेट्रो नेटवर्क को दीर्घकालिक और टिकाऊ बनाना है, ताकि यह आने वाले दशकों तक दिल्ली की परिवहन जरूरतों को पूरा कर सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और अन्य शोध संस्थानों की रिपोर्ट साफ तौर पर बताती है कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह वाहनों से निकलने वाला धुआं है। ऐसे में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि मजबूरी बन चुका है। सरकार का लक्ष्य मेट्रो नेटवर्क को इतना व्यापक और सुविधाजनक बनाना है कि लोगों को निजी वाहन निकालने की आवश्यकता ही महसूस न हो। इसके लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी, बस-मेट्रो समन्वय और समयबद्ध क्रियान्वयन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सरकार इस पूरी पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'नेट जीरो एमिशन' के विजन से जोड़कर देख रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार भिशन मोड में काम कर रही है, ताकि राजधानी को एक पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ परिवहन मॉडल की ओर ले जाया जा सके। उनका कहना है कि आज लिए गए फैसले आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा और बेहतर जीवन की नींव रखेंगे। मेट्रो विस्तार और परिवहन बजट में भारी निवेश के जरिए दिल्ली सरकार ने यह संकेत दे दिया है कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई अब सिर्फ चेतावनियों और प्रतिबंधों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मजबूत बुनियादी ढांचे के सहारे निर्णायक रूप लेगी।

धर्म सत्ता से ऊपर है, राजनीतिक स्वार्थों से दूर रहना ही समाज के हित में—बंगाल में मोहन भागवत का बड़ा संदेश।

से अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे न केवल जनसांख्यिकीय संतुलन प्रभावित होता है, बल्कि सामाजिक तनाव भी बढ़ता है। भागवत ने दो टूक कहा कि हिंदुओं के लिए भारत ही प्रकाशर देश है इमलिंग यद्यां स्वीकार करना है, जिसकी जड़े हिंदुओं और जिसने सदियों से विविधता में एक भावना को मजबूत किया है। मदरसाओं को लेकर भागवत ने कहा कि समय वह है कि शिक्षा व्यवस्था आधुनिक, व्यावरणीय और राष्ट्रवादी मूल्यों से जुड़ी हो। असम सरकार द्वारा मदरसों में जड़े

अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, जो किसी भी दृष्टि से रास्त्रहित में नहीं है। भागवत ने यह भी कहा कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार निभा सकती है, लेकिन उनके संचालन और रखरखाव में सरकारी धन का उपयोग करना न केवल गलत है, बल्कि कानून की भावना के भी खिलाफ है। धर्म को राजनीति और सत्ता से अलग रखना ही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। अपने संबोधन में संघ प्रमुख ने पश्चिम बंगाल की सामाजिक स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यहाँ कटुरपंथी सोच का विस्तार हो रहा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने सीमावर्ती इलाकों

से अवैध धुमपैठ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे न केवल जनसांख्यिकीय संतुलन प्रभावित होता है, बल्कि सामाजिक तनाव भी बढ़ता है। भागवत ने दो टूक कहा कि हिंदुओं के लिए भारत ही एकमात्र देश है, इसलिए यहाँ की सांस्कृतिक और सामाजिक सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रह कथित अत्याचारों का जिक्र करते हुए वैश्वक हिंदु समाज से एकजुट होकर मदद और समर्थन की अपील की। मोहन भागवत ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि आएरएसएस मुस्लिम विरोधी संगठन नहीं, बल्कि राष्ट्रवादी संगठन है, जो भारत की एकता, संस्कृति और मूल्यों की रक्षा के लिए काम करता है। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसका अर्थ किसी पर धर्म थोपना नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान को स्वीकार करना है, जिसकी जड़े हिंदुओं और जिसने सदियों से विविधता में एक भावना को मजबूत किया है। मदरसाओं को लेकर भागवत ने कहा कि समय वह है कि शिक्षा व्यवस्था आधुनिक, व्यावरणीय और राष्ट्रवादी मूल्यों से जुड़ी हो। असम सरकार द्वारा मदरसों से जुड़े का समर्थन करते हुए, कहा कि शिक्षा उद्देश्य बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना आत्मनिर्भर बनाना और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी नागरिक तैयार करना होना चाहिए। जोर देकर कहा कि किसी भी समुदाय किसास तब ही संभव है, जब उसकी व्यवस्था आधुनिक जरूरतों के अनुरूप और समाज को आगे बढ़ाने में सहायता दें। बंगाल दौरे के दौरान दिए गए मोहन के ये व्यापार न केवल धार्मिक और सामाजिक विमर्श को नई दिशा देने वाले माने जाते हैं, बल्कि यह भी संकेत देते हैं कि संघर्ष धर्म और राजनीति के बीच संतुलन रखने और समाज में अनावश्यक टक्कर बचने की पैरवी कर रहा है।

अमेरिका की सुरक्षा पर इस्लामी उग्रवाद की गहरी छाया राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड की कड़ी चेतावनी

The image is a composite. On the right side, a woman with long dark hair and a white blazer is smiling, standing in front of the American flag. On the left side, there is a vertical column of text in Hindi script, which is a transcription of the speech provided above.

સેવાઓનું અધ્યા

जगहों पर क्रिसमस बाजार रद्द किए जा रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि उप्रवाद का भय अब सार्वजनिक जीवन और सांस्कृतिक उत्सवों तक को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है और यहां भी इस्लामी कट्टरपंथ का प्रभाव धीरे-धीरे फैल रहा है। उन्होंने दावा किया कि मिशिगन, मिनियापोलिस और मिनेसोटा जैसे राज्यों में कुछ मौलिक खुलेआम इस्लामी कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं और युवाओं को प्रभावित कर रहे हैं। उनके अनुसार, यह केवल धार्मिक प्रचार का मामला नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित वैचारिक अभियान है, जिसका उद्देश्य युवाओं को कट्टर बनाना और अमेरिकी समाज की मूल संरचना को चुनौती देना है। गबार्ड ने कहा कि युवाओं को निशाना बनाना इस उप्रवादी सोच की सबसे खतरनाक रणनीति है, क्योंकि इससे आने वाली पैदियों की साचे और पहचान प्रभावित होती है।

राष्ट्रीय खुफिया निदेशक ने यह भी दावा किया कि इस वर्ष की शुरुआत में इस्लामिक संगठनों की एक बैठक हुई थी, जिसमें अमेरिका के कई हिस्सों में शरिया कानून लागू करने की मांग

उठाई गई थी। उन्होंने कहा कि ह्यूस्टन जैसे कुछ क्षेत्रों में यह व्यवस्था पहले से ही किसी न किसी रूप में लागू की जा चुकी है। गबार्ड के अनुसार, यह खतरा किसी दूर देश का नहीं, बल्कि अमेरिका की सीमाओं के भीतर मौजूद वास्तविक चुनौती है। उन्होंने पैटरसन, न्यू जर्सी का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां खुद को पहला मुस्लिम शहर बताने पर गर्व किया जाता है, और यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे इस्लामी कानूनों को आम नागरिकों पर थोपने की कोशिश की ओर बढ़ी है।

तुलसी गबार्ड ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि अमेरिका को इस खतरे को नजरअंदाज करने की भूल नहीं करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते इस वैचारिक और सुरक्षा चुनौती का समाना नहीं किया गया, तो यह न केवल अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, बल्कि उसकी सांस्कृतिक पहचान और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भी गंभीर संकट बन सकता है। उनका कहना था कि अब वक्त आ गया है कि इस्लामी आतंकवाद और उग्रवादी विचारधारा के खिलाफ खुलकर, स्पष्ट और एकजुट होकर कार्रवाई की जाए।

‘कुछ सेक्युलर गाओ’ की धमकी से मंच पर हंगामा
‘जागो मा’ गाने पर बंगाल ने उभरा बड़ा विवाद

पूर्वोत्तर को लेकर उकसावे की साजिश, भारत सीमा पर तुर्किये के ड्रोन-अशांत बांग्लादेश से बढ़ी सुरक्षा चुनौती

नई दिल्ली। हिंमा, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक कलह से ज़द्दा रहे बांगलादेश में भारत विरोधी गतिविधियों का ग्राफ तेज़ी से ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि कट्टरपंथी तत्व न केवल भड़काऊ बयान दे रहे हैं, बल्कि भारत की संप्रभुता और सुक्ष्मा को सीधे चुनौती देने वाले कदम भी सामने आ रहे हैं। 'सेवन सिस्टर्स' यानी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर कब्जे जैसी धमकी भरी टिप्पणियों के बीच अब भारत-बांगलादेश सीमा के पास तुर्किये से खरीदे गए उन्नत सैन्य ड्रोन की तैनाती ने नई दिल्ली की चिंताओं को और गहगा कर दिया है। बांगलादेश में इंकलाब मंच के संयोजक शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देश के कई हिस्सों में दिंग्या और अव्यवस्था फैल गई है। इस अशांत माहौल का फायदा उठाकर कुछ कट्टरपंथी और भारत विरोधी संगठन खुलकर नफरत फैलाने में जुट गए हैं। सोशल मीडिया से लेकर सार्वजनिक मंचों तक भारत के खिलाफ उत्क्षावे वाले बयान दिए जा रहे हैं। यहां तक कि ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग पर हमले की धमकियां भी सामने आई हैं, जिन्हें लेकर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, बांगलादेश की यूनास सरकार ने 'तुर्किये से खरीदे गए अत्याधिक 'बेयरकर TB-2' ड्रोन भारत की सीमा के करीब तैनात किए हैं। ये ड्रोन पिछले वर्ष खरीदे गए थे और इन्हें हासिल करने में पाकिस्तान की कथित मध्यस्थता की भूमिका भी बताई जा रही है। सत्ता परिवर्णन के बाद ढाका और इम्लामगाँव के बीच बढ़ती

अखंडता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार-उज-जमान और भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बीच हॉटलाइन पर सीधी बातचीत भी हुई जिसमें सीमा सुरक्षा और हालिया घटनाक्रमों चर्चा की गई। इसके साथ ही दिल्ली में सिंघमालादेश उच्चायोग के बाहर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है, ताकि किसी भी अतिरिक्त घटना को रोका जा सके। भारत सरकार घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं ताकि साफ संकेत दे चुकी है कि उक्सावे, धर्मकीर्ति संन्य दबाव की किसी भी कोशिश का जवाब न देना चाहिए।

गंधर विवाद में बदल गया, जब लोकप्रिय बंगाली गायिका लापानजिता चक्रवर्ती के साथ मंच पर कथित बदसलूकी और धमकी की घटना सामने आई। भगवान्पुर इलाके के एक स्कूल परिसर में शुक्रवार शाम आयोजित इस कार्यक्रम में माहौल तब तनावपूर्ण हो गया, जब गायिका द्वारा 'जागो मां' गीत प्रस्तुत किए जाने के बाद एक स्थानीय व्यक्ति मंच पर चढ़ आया और कथित तौर पर उनसे 'सेक्युलर' गीत गाने की मांग करने लगा। आरोप है कि व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से न केवल कार्यक्रम में व्यवधान डाला, बल्कि महिला कलाकार को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी और शरीरिक हमला करने की कोशिश की। लापानजिता चक्रवर्ती ने इस संबंध में पुलिस में वाली थीं, तभी महबूब मलिक नाम का व्यक्ति अचानक मंच पर आ गया। गायिका के अनुसार, आरोपी आक्रमक लहजे में उनसे बहस करने लगा और कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मंच पर हुई पूरी घटना स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है और आयोजकों द्वारा भी कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है। गायिका ने मांग की है कि इन सभी फुटेज को सुरक्षित किया जाए और एक महिला कलाकार के साथ सार्वजनिक मंच पर हुई बदसलूकी को गंभीर अपराध मानते हुए सख्त कार्रवाई की जाए। घटना सामने आने के बाद यह मामला केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक रंग भी लेता चला गया। भारतीय है और उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। भाजपा नेता शंकुदेव पांडा ने दावा किया कि घटना के बाद गायिका और उनकी टीम में भय का माहौल बन गया, जिसके चलते उन्हें कार्यक्रम के तुरंत बाद देर रात कोलकाता लौटना पड़ा। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि शुरुआती स्तर पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेने के बजाय माफी मांगकर सुलझाने की कोशिश की, जिससे कलाकारों में और असुरक्षा की भावना पैदा हुई। पुलिस प्रशासन ने हालांकि इन आरोपों के बीच कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ईस्ट मिदानपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मिथुन डे ने पुष्टि की है कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपी की गिरफतारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

